

अनुशासन समिति राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

मु0नं० 218/2021

अनुशासन समिति परिवाद संख्या 31/2022

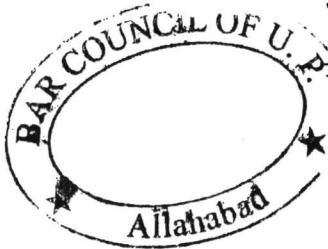
मुशीर अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व० मुनीर अहमद सिद्दीकी निवासी
60ए/9डी/5सी/2एफ म्योराबाद, जनपद प्रयागराज।.....परिवादी

बनाम

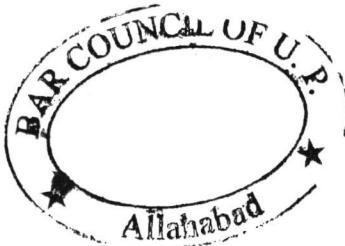
रोशन जहाँ सिद्दीकी पंजीकरण संख्या यू०पी० 0406/2015, निवासी
390/7/1 साहिल कालोनी राजापुर, जनपद प्रयागराज।विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय

समिति के समक्ष मुशीर अहमद सिद्दीकी द्वारा विपक्षी रोशन जहाँ सिद्दीकी के विरुद्ध धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है कि रोशन जहाँ सिद्दीकी का लाइसेन्स निरस्त कर दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें। तथ्यों के सापेक्ष मे परिवादी का कथन है कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पंजीकरण फार्म मे तथ्यो को छिपाया गया जो कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24ए के विरुद्ध और विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध 7 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है व इसके अतिरिक्त विपक्षी अधिवक्ता ने सदैव अधिवक्ता आचरण के विरुद्ध कार्य किये है और फर्जी तरीके से हलफनामो को दाखिल किया। परिवादी का यह भी कहना है कि विपक्षी की मूल डिग्री का भी परिशीलन किया जाय और परिवाद पत्र की धारा 6 में उल्लिखित किया है कि तथ्यो को छिपाकर अधिवक्ता की आड में विपक्षी द्वारा जमीनो पर अवैध कब्जे धन वसूली चरस गांजे का संगीन अपराध किया जा रहा है और विपक्षी अधिवक्ता के समस्त कृत्य



[Signature]

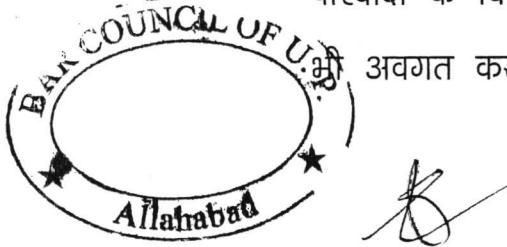


वकालत मा० उच्च न्यायालय मे कर रही है। समिति द्वारा परिवाद पत्र व विपक्षी के प्रतिउत्तर पूरक शपथ पत्र व संलग्नको का अवलोकन किया गया और समिति की राय में तथ्यो के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1. क्या परिवादी को विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने का अधिकार है?
2. क्या विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 ए के विरुद्ध कार्य किया गया है?
3. क्या विपक्षी अधिवक्ता ने धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत कदाचरण किया है?
4. क्या परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है? निर्णय की सुगमता के लिये समिति द्वारा बिन्दुवार आदेश पारित किया जा रहा है?

निस्तारण

वाद बिन्दु संख्या 1:- परिवादी द्वारा धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिवाद को दाखिल करते हुये विपक्षी के लाइसेन्स को निरस्त करने की मांग की है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को नियमतः परिवाद दाखिल करने का समुचित सिविल अधिकार प्राप्त है और उसके द्वारा समुचित न्याय शुल्क भी अदा किया गया है। प्रतिउत्तर में विपक्षी अधिवक्ता ने ऐसे कोई साक्ष्य और स्पष्ट कथन नहीं उल्लिखित नहीं किये हैं जिससे यह साबित होता हो कि परिवादी को विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अस्तु परिवादी के पक्ष



आचरण विहीन है इस कारण लाइसेन्स निरस्त किया जाय। परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता के विरुद्ध दाखिल आपराधिक मुकदमों की सूची दाखिल की है। विपक्षी अधिवक्ता ने अपना काउण्टर शपथ पत्र दाखिल करके स्पष्टीकरण दिया है कि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप तथ्य विहीन हैं और उसकी व्यक्तिगत रंजिश के कारण परिवादी ने मुकदमों को अनावश्यक रूप से दिखलाया है जो कि अभी किसी भी व्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं किये गये हैं। विपक्षी अधिवक्ता ने अपने ऊपर लगे सभी मुकदमों के बावत स्पष्ट कथन जरिये शपथ पत्र कहे और परिवाद पत्र को खण्डित करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त अपने पूरक शपथ पत्र में परिवादी ने लिखित किया है कि विपक्षी अधिवक्ता ने एक अपराधी की तरह सामान्य लोगों के विरुद्ध पिछले 12 वर्षों से कई मुकदमों लिखवाये जिसमें बलात्कार, छेड़खानी और पाक्सो एकट से सम्बन्धित भी मुकदमों हैं इस प्रकार विपक्षी द्वारा लगभग 11 मुकदमों आम लोगों के विरुद्ध लिखवाये गये जिसके सम्बन्ध में परिवादी ने प्रपत्र दाखिल किये हैं और विपक्षी रोशन जहां का आपराधिक इतिहास भी पूरक शपथ पत्र में संलग्नक-18 के माध्यम से 12 मुकदमों का दाखिल किया। संलग्नक 19 के माध्यम से विपक्षी के विरुद्ध एन०वी०डब्लू० के आदेश इत्यादि दाखिल किये हैं जिसका अपने प्रतिउत्तर में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा खण्डन किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी अधिवक्ता ने 27.08.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये परिवादी के विरुद्ध अवगत कराया है कि वह करीबी रिश्तेदार होने के कारण उपरोक्त झूठी शिकायत कर रहा है और महिला की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी के विरुद्ध मुकदमों के दाखिल करने की बात उल्लिखित की और यह भी अवगत कराया है कि वह माननीय उच्च व्यायालय की सदस्य भी है और

में वाद बिन्दु संख्या 1 सकारात्मक रूप से व विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध नाकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 2:- परिवादी के परिवाद पत्र में इस आशय का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि विपक्षी अधिवक्ता ने धारा 24 ए अधिनियम 1961 के प्राविधानों का उल्लंघन किया है। समिति ने विपक्षी अधिवक्ता की मूल पंजीकरण पत्रावली को तलब कर उसका परिशीलन किया। दाखिल घोषणा और शपथ पत्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपक्षी अधिवक्ता ने स्वयं के ऊपर लगे हुये आपराधिक मुकदमों के सम्बन्ध में कोई भी शपथ पत्र या घोषणापत्र राज्य विधिज्ञ परिषद को न तो पूर्व में और न ही बाद में प्रस्तुत किया। अतः इस तथ्य का खण्ड नहीं किया जा सकता कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने ऊपर लगे हुये गम्भीर आपराधिक मुकदमों की कोई सूचना परिषद को उपलब्ध करायी गयी अतः वाद बिन्दु संख्या 2 विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है व रोल कमेटी को माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्रेषित करने की संस्तुति भी की जाती है।

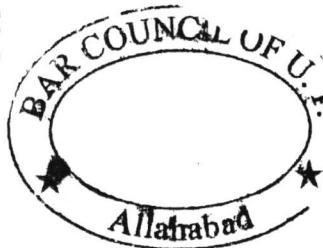
वाद बिन्दु संख्या 3:- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र और विपक्षी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर शपथ पत्र में लिखित कथनों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता ने भरण पोषण वाद संख्या 253 सन 2008 धारा 125 सीआर०पी०सी० अपने पति संख्या 3 मो० शाहिद के विरुद्ध दाखिल किया और मु०अ०सं० 123 सन 2016 थाना कैण्ट मे पारित आदेश दिनांकित 03.04.2018 जो कि विपक्षी अधिवक्ता के पति संख्या-5 है के विरुद्ध पाक्सो एक्ट मे दाखिल किया गया और उक्त तिथि को उसका जमानत प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया। व इसके अतिरिक्त वाद सं० 362 सन 2000 में विपक्षी ने मो० आसिम पति संख्या-2 के विरुद्ध भरण पोषण का



[Handwritten signature]

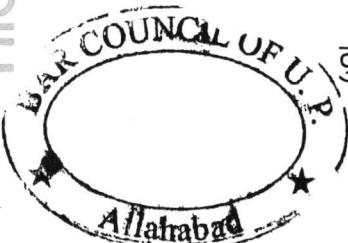
एक वाद दाखिल किया। पूरक शपथ पत्र के संलग्न संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट कि रोशन जहां के पति संख्या-4 का नाम नबाब खाँ उर्फ गुड़ू लिखा है और पत्र के अवलोकन से विपक्षी अधिवक्ता के तिहाड जेल में विरुद्ध होने की भी बात प्रकाश में आती है इसके अतिरिक्त संलग्न 9 प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि विपक्षी द्वारा करायी गयी व संलग्नक 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता ने कई लोगों के विरुद्ध मुकदमें लिखवाये हैं।

सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत संलग्न और साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी के भाई द्वारा रूपयों के लेने-देने में विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध धारा 406, 506 आई.पी.सी. का वाद दाखिल किया था जिस कारण विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी पुत्री के माध्यम से पास्को एक्ट में मुकदमा परिवादी व उसके भाई के ऊपर लिखवा दिया कि रूपया न देना पड़ा। परिवादी के भाई के विरुद्ध दाखिल पास्को वाद में माननीय उच्च व्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रचलित है। यह कृत्य पूरी तरह से मारल टरपीट्यूड के अन्तर्गत आता है और निश्चित रूप से अधिवक्ता होने का लाभ विपक्षी द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति द्वारा इस आशय की धारणा नहीं की जा सकती कि कोई एक व्यक्ति इस तरह से आचार व्यवहार करे कि वह समाज के अनेक प्रतिष्ठित और परिजनों के विरुद्ध मुकदमें आदि लिखा पाये और यह भी धारणा नहीं की जा सकती कि समाज के सभी प्रतिष्ठित और अनेक लोग एक ही व्यक्ति के विरुद्ध अकारण मुकदमें लिखवाये। पत्रावली में दाखिल तथ्यों और एफ0आई0आर0 से यह पता चलता है कि किस तरह विपक्षी ने अनेक लोगों का उत्पीड़न किया और इस तथ्य को व्यायालय के जमानत प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांकित 03.04.2018



से भी बल मिलता है कि विपक्षी ने अपनी पुत्री के माध्यम से पति के विरुद्ध पाक्सो एक्ट मे मुकदमा लिखाया और सुलह करके 164 सीआर०पी०सी० मे झूठा बयान दिया और मात्र संलग्नक सं०७ फोटो चित्र जो कि एक पिता और पुत्री के प्रेम का परिचायक है को आधार बना लिया गया। भारतीय समाज में स्त्रीयों को अत्यन्त सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि स्त्रीया अपने परिवार और पुत्र व पुत्रियों की प्रथम शिक्षक होती है। परन्तु विपक्षी के विरुद्ध पाये गये साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी ने अभी तक के अपने जीवन काल में 5 व्यक्तियों से विवाह किया है और स्वयं तिहाड़ जेल मे निरुद्ध रही है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध हनीट्रैप के मामले मे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की। जिसके सम्बन्ध में गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये हैं। विपक्षी यदि पेशे से अधिवक्ता न हो तो क्या उपरोक्त कृत्यों को किये जाने पर वह सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार कर सकती थी और यदि एक सामान्य व्यक्ति उपरोक्त समस्त अपराध कारित करता है तो वह राज्य सरकार द्वारा व केन्द्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के अन्तर्गत एक गम्भीर अपराध की श्रेणी मे आता है। परन्तु यहां पर विपक्षी एक नागरिक होने के साथ साथ अधिवक्ता है और अधिवक्ता होने के कारण व्यायिक प्रक्रिया का एक भाग बन जाती है। भारतीय व्यायिक प्रक्रिया में और भारतीय समाज में अधिवक्ताओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक अधिवक्ता जो कि पीडित को व्याय दिलाने का कार्य करता है और अपने व्यक्तित्व के आधार पर समाज को दिशा और दशा देने का कार्य करता है। परन्तु वर्तमान स्थिति में विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध दाखिल साक्ष्यों के आधार पर समिति को लिखने मे यह खेद व्यक्त करना पढ़ रहा है कि हमारे समाज





में उक्त तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति अधिवक्ता समाज में सम्मिलित हो गये हैं और राज्य विधिज्ञ परिषद की यह जिम्मेदारी है कि वह अधिनियम में प्राप्त अपनी शक्तियों का सकारात्मक रूप से पालन करे। क्या समिति इस कारण विपक्षी अधिवक्ता के प्रतिउत्तर को संज्ञान लेकर क्षमा कर देगी कि वह एक महिला है जबकि संविधान पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं और विपक्षी नागरिक होने के साथ साथ समाज की एक विशिष्ट स्तम्भ का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है। विपक्षी अधिवक्ता ने 5 व्यक्तियों के विलङ्घ जिन्हे वह अपना पति स्वीकारती है कार्यवाही की व अन्य अनेक व्यक्तियों के विलङ्घ मुकदमें लिखाये और अपनी पुत्री को ब्लेकमेलिंग के कार्यों में लिप्त किया जो कि सभ्य समाज का सबसे घृणित कार्य है कि एक महिला जो कि अधिवक्ता भी है और कानून को जानने वाली है उसने अपनी पुत्री को अपराध का हथियार बनाया और भारतीय कानून से प्राप्त उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जो महिलाओं को विशिष्ट रूप से प्राप्त है। समिति समस्त पत्रावली का बारीकी से परिशीलन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विपक्षी एक सामान्य नागरिक होती तो निश्चित तौर पर एक दर्जन से अधिक मुकदमों में न तो लिप्त रहती और न ही दूसरे व्यक्तियों के विलङ्घ मुकदमें करती जबकि अन्य व्यक्तियों का कोई भी सीधा सम्बन्ध विपक्षी के साथ नहीं था। अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी ने अपने अधिवक्ता होने का दुरुपयोग नहीं किया जबकि वह समस्त तथ्यों से भली भांति परिचित थी और समस्त कानूनों को अधिवक्ता होने के कारण जानकारी में रखती थी उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निश्चित रूप से अपने व्यवसाय का दुरुपयोग किया गया और अधिवक्ता समाज के साथ साथ व्यायिक प्रक्रिया का

तथ्यो को छिपाकर अपने अधिकारी का दुरुपयोग किया गया। क्योंकि सामान्य व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वह उपरोक्त तरह से मुकदमों को लिखवाकर व्यक्तियों को ब्लैक मेल कर सकती है। अतः समिति वाद बिन्दु संख्या का निस्तारण परिवादी के पक्ष में और तथा विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध नकारात्मक निस्तारित करती है।

वाद बिन्दु संख्या 4:- उपरोक्त समस्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है और तथ्यों तथा साक्षों की गम्भीरता को देखते हुये विपक्षी अधिवक्ता के प्रतिउत्तर में कोई बल नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

समिति द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुये विपक्षी अधिवक्ता का लाइसेन्स/ अनुज्ञाप्ति /अधिवक्ता पंजीकरण अग्रिम 10 वर्षों के लिये निलम्बित किया जाता है। विपक्षी अधिवक्ता को सम्पूर्ण भारत वर्ष में अग्रिम 10 वर्षों के लिये अधिवक्तावृत्त हेतु प्रतिबंधित किया जाता है व इसके अतिरिक्त आदेश की प्रति मय मूल पत्रावली को माननीय अध्यक्ष राज्य विधिज्ञ परिषद को इस आशय की संस्तुति से प्रेषित की जाती है कि महोदय धारा 24 ए अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सक्षम रोल कमेटी के समक्ष पत्रावली प्रेषित करेंगे।



दिनांक: ०५.०८.२०२३

४०७५०-

४०७५८

TRUE COPY

आनुभाष अधिकारी
अनुशासन समिति
बार कॉर्सिल भौफ उच्चप्र०, प्रयागराज